

गृह मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार  
विंग के अधिकारियों के वेतन  
तथा भत्तों पर किया  
गया व्यय

4716. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :  
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार विंग (एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म विंग) में कितने अधिकारी तथा कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) उस विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर वर्ष 1983-84 के दौरान कितनी राशि खर्च की जा रही है तथा वर्ष 1982-83 में इन शीर्षों के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च की गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) वहां 154 कर्मचारी हैं जिनमें से 36 राजपत्रित अधिकारी हैं ।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान वेतन और भत्तों के लिए 26,50,000/- रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है जबकि वर्ष 1982-83 के दौरान इन शीर्षों के अन्तर्गत 27,58, 219.00 रुपए का खर्च किया गया था ।

#### Assessment of Various Programmes by Programme Evaluation Organisation

4717. SHRI BABURAO PRANJPE :  
SHRIMATI SANYOGITA  
RANE :

Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether the Programme Evaluation Organisation (P.E.O.) in the Plan-

ning Commission is charged with the most important function of assessment of various programmes undertaken as Plan schemes:

(b) if so, whether a Committee under the Chairmanship of Shri P. R. Dubhashi made an in-depth study of the functioning of this organisation with a view to make it more purposeful;

(c) the main recommendations of the Committee, those accepted and implemented and which are awaiting acceptance and/or implementation; and

(d) reasons for non-acceptance/implementation of recommendations ?

THE MINISTER OF PLANNING  
(SHRI S. B. CHAVAN) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Copies of the Report containing the recommendations are available in the Parliament Library. The post of Joint Secretary in the P.E.O. was re-designated as Evaluation Adviser as recommended by the Committee (appearing at para 5.34 of the Report). All the other recommendations are still awaiting acceptance.

(d) The question does not arise.

#### हिन्दी पुस्तकों की खरीद

4718. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालयों के ग्रन्थालय ने गत दो वर्षों के दौरान हिन्दी की कोई पुस्तक नहीं खरीदी है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि संबंधित अधिकारियों का खर्चा हिन्दी पुस्तकों की खरीद के मामले में पूर्णतया उदासीन है जबकि अंग्रेजी पुस्तकों की खरीद के लिये लाखों रुपये का प्रावधान किया गया है ?